



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1937 (श10)
(सं0 पटना 919) पटना, मंगलवार, 11 अगस्त 2015

vki nk i cdku folkkx

अधिसूचनाएं
25 eb 2015

fcgkj d'f'k l dVxLr fdl ku l gk; rk ; kstuk

सं० 01/गै0प्रा0आ0-01/2015/1946-आ0प्र0—बिहार राज्य की जनसंख्या का 80% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है तथा उनमें से अधिकांश जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। बिहार राज्य में लघु एवं सीमान्त जोत वाले कृषकों की संख्या बड़े कृषकों से कहीं ज्यादा है, परन्तु भूमि-स्वामित्व के मामले में बड़े कृषक काफी आगे हैं। चूंकि बहुत कम बड़े किसान सीधे तौर पर अपनी भूमि पर खेती करते हैं, वे खेती के लिए अपनी भूमि भाड़े पर लघु एवं सीमान्त किसानों को अथवा बटाई पर दे देते हैं। इसके कारण यद्यपि लघु एवं सीमान्त किसान तथा बटाईदार जोत की अधिक भूमि धारित नहीं करते हैं, तथापि वे कृषि संकट से अपेक्षाकृत अधिक ग्रस्त होते हैं। बिहार राज्य में कृषि संकट ज्यादातर, प्राकृतिक/गैर प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसलों की क्षति, कृषि ऋण की कमी, बटाईदारों अथवा भाड़े पर लिये गये भूमि में जोत करने वाले किसानों को संस्थागत कृषि ऋण उपलब्ध नहीं होना, लागत मूल्यों में वृद्धि, (input), कृषि उत्पादों के लिए प्रतिकूल बाजार की परिस्थितियों एवं असमान कृषि-संबंधों के कारण उत्पन्न होता है। देश के अन्य राज्यों में हॉलाकि कृषि संकट के कारण कृषकों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएँ की हैं, परन्तु बिहार राज्य में ऐसी दुखद घटनाएँ नहीं हुई हैं। लेकिन, हाल में इस प्रकार की एक घटना सरकार के संज्ञान में आयी है।

कृषि संकट एवं उससे उद्भूत परिणामों के सक्रिय समाधान आवश्यक हैं। अतएव राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि कृषि संकट के कारकों को रोकने के उपाय किये जायें तथा आत्म-हत्या करने वाले किसानों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराया जाय। राज्य सरकार की समझ है कि आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार के सदस्यों को सुरक्षा तंत्र से आच्छादित किया जाय एवं यह कि Vulnerable होने के कारण राज्य के संसाधनों पर उनका हक है।

अतएव, प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने तथा कृषि संकट के रोकथाम के उपाय करने के उद्देश्य से fcgkj l dVxLr fdl ku l gk; rk ; kstuk 2015 नामक योजना का सूत्रण निम्न प्रकार से किया जाता है:—

fcgkj l dVxLr fdl ku l gk; rk ; kstuk 2015

1- foLrkj , oa ; kstuk dk i dUk gkuk %Extent and Commencement %A यह योजना बिहार राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी तथा यदि शहरी क्षेत्रों के आस-पास कृषि संबंधित कार्य किये जाते हैं, तो वहाँ भी लागू होगी। यह योजना 01 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी।

2- **ifjHkk"kk, A&** इस योजना में, जबतक कि अन्य परिप्रेक्ष्य में अभिप्रेत न हो—

- (i) ****vij l ekgÜkkz**** से तात्पर्य है वैसा पदाधिकारी जो राज्य सरकार के द्वारा जिले में अपर समाहर्ता के रूप में कार्य करने के लिए पदाविहित हो।
- (ii) ****df"k mRiknu vk; Ør**** से तात्पर्य है वैसा पदाधिकारी जो इस रूप में राज्य सरकार के द्वारा पदाविहित हो।
- (iii) ****vpy vf/kdkjh**** से तात्पर्य है वैसा पदाधिकारी जो इस रूप में राज्य सरकार के द्वारा पदाविहित हो।
- (iv) ****i[kM fodkl i nkf/kdkjh**** से तात्पर्य है वैसा पदाधिकारी जो इस रूप में राज्य सरकार के द्वारा पदाविहित हो।
- (v) ****vl fud 'kY; fpdfRI d&l g&e[; fpdfRI k i nkf/kdkjh**** से तात्पर्य है वैसा पदाधिकारी जो इस रूप में राज्य सरकार के द्वारा पदाविहित हो।
- (vi) ****vkink i dku foHkkx**** से तात्पर्य है राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग।
- (vii) ****df"k foHkkx**** से तात्पर्य है राज्य सरकार का कृषि विभाग।
- (viii) ****i 'kq , oa eRL; l d k/ku foHkkx**** से तात्पर्य है राज्य सरकार का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।
- (ix) ****l gdfjrk foHkkx**** से तात्पर्य है राज्य सरकार का सहकारिता विभाग।
- (x) ****jktLo , oa Hkfe l qkj foHkkx**** से तात्पर्य है राज्य सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
- (xi) ****fityk i nkf/kdkjh**** से अभिप्रेत है किसी जिले का दंडाधिकारी—सह—समाहर्ता।
- (xii) ****fityk df"k i nkf/kdkjh**** से तात्पर्य है सम्बन्धित जिला का जिला कृषि पदाधिकारी।
- (xiii) ****fdl ku**** से तात्पर्य है वैसे कृषक जो निजी कृषि भूमि को अथवा बटाईदार के रूप में कृषि कार्य करता हो तथा इसमें उसके परिवार के वैसे सभी सदस्य शामिल होंगे जो कृषक अथवा बटाईधारी के साथ वैसी भूमि पर कार्य करते हो।
- (xiv) **bd"k l dVB** से तात्पर्य है प्राकृतिक एवं मनुष्य जननित आपदाओं के कारण फसल की क्षति अथवा हानि, कृषि संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ी किसान की ऋण ग्रस्तता, लागत मूल्यों में वृद्धि के कारण कृषि उत्पादों की उत्पादकता में कमी अथवा प्रतिकूल बाजार स्थितियों से कृषि उत्पादों की बिक्री पर असर अथवा असमान कृषि— संबंधों के फलस्वरूप कृषि संकट का उत्पन्न होना। परन्तु, यह सूची व्याख्यात्मक (illustrative) है, संपूर्ण (exhaustive) नहीं।
- (xv) ****e[k; k**** से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो बिहार पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में मुखिया का कार्य करता हो।
- (xvi) ****i fyl v/kh{kd**** से तात्पर्य है किसी जिले का पुलिस अधीक्षक।
- (xvii) ****jkt; l jdkj**** से तात्पर्य है बिहार सरकार।

df"k l dV ds dkj .k vkRegR; k djus okys fdl kuka ds i fjokjka dks vuqg vuqku , oa vll; ykHkka dk Hkqrku djus dh uhfr

3. आत्महत्या करने वाले किसान का निकटतम सम्बन्धी (next-of-kin) इस योजना के अन्तर्गत प्रावधानित अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

4. स्थानीय ग्राम पंचायत के मुखिया/सरपंच एवं ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी के सदस्य, यथा स्थिति, का यह कर्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत में कृषि संकट के फलस्वरूप होनेवाली आत्महत्याओं की सूचना तत्परता से तथा बिना किसी विलम्ब के स्थानीय थाना सम्बन्धित अंचलाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे।

5. सम्बन्धित अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा स्थानीय थाना का थानाध्यक्ष मुखिया अथवा किसी अन्य श्रोत से सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद यह पड़ताल करेंगे कि वैसे आत्महत्या कृषि संकट के कारण हुई अथवा नहीं एवं यदि कृषि संकट के कारण हुई है तो उस कृषि संकट की विशिष्टियाँ क्या हैं ?

6. यदि किसान ने कृषि संकट के कारण आत्महत्या किया हो तो अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष तत्परता से इसकी सूचना जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को देंगे। तदुपरान्त एक संयुक्त औपचारिक जाँच प्रतिवेदन भी समर्पित करेंगे। यह सूचना अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी भेजी जायेगी।

7. औपचारिक अथवा अन्य सूचना प्राप्ति के पश्चात जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अविलम्ब आत्महत्या करनेवाले किसान के परिवार से मिलेंगे तथा मृत्यु के कारणों का पड़ताल करेंगे। यदि कृषि संकट के कारण मृत्यु हुई हो तो राज्य सरकार को तदुनुरूप सूचित किया जायेगा।

8. जिला पदाधिकारी आवश्यक समझे तो कृषि संकट के विभिन्न आयामों जिनके कारण मृत्यु हुई है कि गहराई से जाँच करायेंगे।

9. इस योजना के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया जायेगा जो कृषि संकट के कारण होनेवाले किसानों की आत्महत्याओं के सभी मामलों पर विचार करेंगे। पुलिस अधीक्षक, असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी तथा अपर समाहर्ता इस स्थायी समिति के सदस्य होंगे एवं अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन इसके सचिव होंगे।

10. यदि स्थायी समिति प्राप्त प्रतिवेदनों तथा वरीय पदाधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर संतुष्ट होती है कि कृषि संकट के कारण किसान ने आत्महत्या की है तो मृतक के निकटतम आश्रित को जिला पदाधिकारी के द्वारा निम्न लाभ दिये जायेंगे—

- (i) आर्थिक असुरक्षा के न्यूनीकरण एवं तात्कालिक वित्तीय संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार के ****i kfjokfjd ykllk ; kst uk **** के वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत तत्परता से लाभ दिये जायेंगे।
- (ii) मृतक किसान की विधवा को राज्य सरकार की विधवा पेंशन योजना के वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत किया जायेगा।
- (iii) मृतक के निकटतम आश्रित (next-of-kin) के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अनुग्रह अनुदान के रूप में 4 लाख रुपये की राशि वैसी योजना में जमा की जायेगी जिसमें खाताधारक को वित्तीय सहायता के रूप में मासिक ब्याज प्राप्त हो सके।
- (iv) 1 लाख रुपये की सीमा के अन्तर्गत एक मुश्त ऋण समझौता लेनदारों (Creditors) के साथ किया जायेगा।

11. आपदा प्रबंधन विभाग के बजटीय उपबंध में से अनुग्रह अनुदान तथा ऋण समझौता के लिए सम्बन्धित जिला पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी।

12. अनुग्रह अनुदान की राशि वैसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी जो मृतक के निकटतम आश्रित (next- of- kin) को सर्वाधिक लाभ पहुँचा सके।

13. स्थायी समिति के द्वारा कागजातों एवं अन्य सबूतों का परिक्षण कर ऋण समझौता की राशि निर्धारित की जायेगी तथा लेनदारों (Creditors) के साथ ऋण समझौता के पूर्व एक निश्चित निष्कर्ष निर्धारित कर लिया जायेगा। यदि मृतक के द्वारा लेनदारों (Creditors) के साथ कोई बंधपत्र (Mortgage Deed) निष्पादित किया गया हो तो वह बंधपत्र (Mortgage Deed) मृतक के निकटतम आश्रित (next- of- kin) को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा तथा ऋण समझौता के पूर्व लेनदार के द्वारा मोचन विलेख निष्पादित किया जायेगा।

14. इस योजना के अन्तर्गत दिये जानेवाले लाभ, यदि लागू हो तो है तो संकटग्रस्त परिवार को आत्महत्या की सूचना प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अन्दर दे दिये जायेंगे।

df'k l dVxLr ifjokfjd s i pLFkki u dh uhfr

15. सामान्य रूप से स्थायी समिति तथा विशेष रूप से जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कृषि विभाग के कर्मि संकटग्रस्त परिवारों के साथ एक वर्ष अथवा उस अवधि तक कार्य करेंगे जो संकटग्रस्त परिवार को संकट से उबारने के लिए आवश्यक है। ये कर्मि कृषि ऋण, कृषि बीमा लाभ, कृषि तकनीक उत्पादक सामग्री (input) के उपयोग, कृषि के वैविधिकरण (Diversification), उत्पाद सुविधाओं की अधिप्राप्ति को संकटग्रस्त परिवारों तक पहुँचने में सहायता करेंगे एवं भूमि सम्बन्धी वैसी मामले जो उन्हें प्रभावित करते हो का समाधान करेंगे।

16. सामान्य रूप से स्थायी समिति तथा विशेष रूप से जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संकटग्रस्त परिवार कृषि के विकासात्मक योजनाओं एवं अन्य सम्बन्धी विभागों की योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) से आच्छादित हो जाए।

df'k l dV ds jkdFkke ds mik;

17. जिला ऋण योजना के अनुसार किसानों के लिए संस्थागत ऋण के प्रोत्साहन, विस्तारीकरण एवं अनुश्रवण करने तथा सभी सुयोग्य किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) एवं जिलास्तरीय बैंकर्स समिति (DLBC) जैसे मंचों का भरपूर उपयोग किया जायेगा।

18. कृषि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार के कृषि रोड मैप के अन्तर्गत लाभ तथा अन्य राज्यों एवं केन्द्र सरकार की कृषि से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन, वैसी क्षेत्रों, जो कृषि जलवायु तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के कारण कृषि संकट के लिए भेद्य है, में केंद्रित होगा।

19. राज्यस्तर पर कृषि संकट की रोकथाम के लिए उपायों पर सुझाव देने एवं इस योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति का गठन किया जायेगा। कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सहकारिता विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव तथा प्रधान सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। कृषि निदेशक इस समिति के संयोजक होंगे।

foopuk rFkk dfBukb; k dk fuokj.k

20. यदि इस योजना की विवेचना अथवा इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आपदा प्रबंधन विभाग विवेचना के लिए सक्षम होगा एवं इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निदेश जारी करेगा। विभाग का निर्णय वैसे सभी मामलों में अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
व्यास जी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 25th May, 2015

Bihar Scheme for Assistance to Farmers in Farm Distress

No. 01/UN0 Dis0/01/2015/1947/DM—Over 80 percent of Bihar population lives in the rural areas and most of them are dependant for their livelihood on agriculture. The number of cultivators in Bihar owning small and marginal landholdings outweighs the number of big farmers but the landholding ownership is skewed towards big farmers. Since very few big farmers directly cultivate their own land, they rent out their farms to the small and marginal farmers or to the sharecroppers for actual cultivation. This phenomenon presents a diverse agricultural situation where small and marginal farmers as well as sharecroppers though not holding much land bear the consequences of farm distress. The farm distress in Bihar occurs mostly due to crop failures on account of natural disasters and manmade disasters, lack of credit, no institutional credit support to the sharecropper or farmer tilling the land taken on rent, increased input costs, adverse market conditions for farm produce and inequitable agrarian relations etc. In several States in India farm distress has caused large scale farmer suicide, but such tragic incidents so far had not taken place in Bihar. However, one instance of farmer suicide arising out of farm distress has been brought to the notice of the State Government recently.

The issue of farm distress and its likely consequences require proactive solutions. The State Government, therefore, considers it expedient to take preventive measures to address the factors causing farm distress and provide ex gratia and extend other benefits to the family of the farmers committing suicide. In the opinion of the State Government the family members of farmers committing suicide should be covered under safety net and being vulnerable have entitlement to the State's resources.

Hence, a scheme titled "Bihar Scheme for Assistance to Farmers in Farm Distress, 2015" is formulated here as under to provide assistance to such families and take measures to prevent farm distress:

"Bihar Scheme for Assistance to Farmers in Farm Distress, 2015"

1. Extent and Commencement of the Scheme

This scheme shall extend to the whole of rural areas in the State of Bihar and also applicable in case of agricultural activities undertaken in the near vicinity of urban areas. The scheme shall be effective from First April, 2015.

2. Definition:—In this scheme, unless the context otherwise implies,

- (i) **"Additional Collector"** shall mean the officer as such designated by the State Government to discharge the functions of Additional Collector in a district.
- (ii) **"Agriculture Production Commissioner"** shall mean the officer as such designated by the State Government.
- (iii) **"Anchal Adhikari"** shall mean the officer designated as such by the State Government.
- (iv) **"Block Development Officer"** shall mean the officer as such designated by the State Government.
- (v) **"Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer"** shall mean the officer designated as such by the State Government.
- (vi) **"Disaster Management Department"** shall mean the Disaster Management Department of the State Government.
- (vii) **"Department of Agriculture"** shall mean the officer designated as such by the State Government.
- (viii) **"Department of Animal and Fisheries Resources"** shall mean the Department of Animal and Fisheries Resources of the State Government.

- (ix) **“Department of Cooperation”** shall mean the Department of Cooperation of the State Government.
- (x) **“Department of Revenue and Land Reforms”** shall mean the Department of Revenue and Land Reforms of the State Government.
- (xi) **“District Magistrate”** shall mean the District Magistrate and Collector of a district.
- (xii) **“District Agriculture Officer”** shall mean the District Agriculture Officer of the district concerned.
- (xiii) **“Farmer”** shall mean a cultivator who works on his own farm land or on the farm land taken on rent or a sharecropper, and shall include every member of the family of such cultivator or the sharecropper who works with him on such farm lands.
- (xiv) **“Farm Distress”** shall mean loss or failure of crop due to natural or man-made disasters, indebtedness of the farmer directly connected to his agricultural activities, loss of productivity of the farm produce due to increased input costs or adverse market conditions affecting sale of farm produce of the farmers or conditions of distress arising out of inequitable agrarian relationships. This list is, however, illustrative and not exhaustive.
- (xv) **“Mukhiya”** shall mean the person working as mukhiya of a gram panchayat under the Bihar Panchayati Raj Act.
- (xvi) **“Superintendent of Police”** shall mean the Superintendent of Police of the district.
- (xvii) **“State Government”** shall mean the Government of Bihar.

Policy to pay Ex-Gratia and other benefits to the family of farmer committing suicide due to farm distress

3. The next-of-kin of a farmer committing suicide due to farm distress shall be entitled to receive an ex-gratia and other benefits as provided under the Scheme.

4. It shall be the duty of the Mukhiya, Sarpanch and ward members of the local Gram Panchayat to report any such case of farmer suicide occurring within the territorial jurisdiction of the concerned Gram Panchayat due to farm distress promptly and without delay to the local police station, Anchal Adhikari and Block Development Officer.

5. The concerned Anchal Adhikari and Block Development Officer along with the Officer-in-Charge of the local police station shall visit the family of such farmer immediately upon receipt of information from Mukhiya, Sarpanch, ward members of the concerned Gram Panchayat or from any other source and enquire whether such suicide has been committed due to farm distress and if so, what has been the specific nature of the farm distress.

6. If the farmer suicide has occurred due to farm distress, the District Magistrate and Superintendent of Police shall be informed promptly by the Anchal Adhikari, Block Development Officer and Officer jointly followed by the joint formal enquiry report. This information shall also be sent to the concerned Sub divisional Officer and the Sub Divisional Police Officer.

7. Upon receipt of such information formally or otherwise, the District Magistrate and Superintendent of Police shall immediately visit the family of the farmer committing suicide and enquire about the causes of such death. If such death has occurred due to farm distress, the State Government shall be informed accordingly.

8. The District Magistrate, if he thinks desirable, shall cause an in-depth enquiry made about the facets of the farm distress causing such death.

9. A standing committee headed by District Magistrate to consider all cases of the farmer suicide due to farm distress promptly shall stand constituted in all districts of Bihar under these Rules. Superintendent of Police, Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, District Agriculture Officer and Additional Collector shall be the members of the standing Committee and Additional District Magistrate dealing with Disaster Management shall be the Member-Secretary.

10. If the standing committee after due consideration of the reports received or visits made by the senior officers is satisfied that the farmer suicide has occurred due to farm distress, following benefits shall be extended to the next-of-kin of the deceased by the District Magistrate:

- (i) To mitigate the sense of economic insecurity and tide over the immediate financial distress, monetary assistance under the extant provisions of “Family Benefit Scheme” of the State Government shall be promptly extended.
- (ii) The widow of the deceased farmer shall be sanctioned pension under the extant provisions of widow pension scheme of the State Government.
- (iii) An ex-gratia of Rs 4 (lakh) shall be deposited in the name of the next-of-kin to create a fund with a Nationalized Bank under a scheme which should provide monthly interest to the account holder as a financial relief.
- (iv) Loan settlement upto a ceiling of Rs one lakh as one time settlement to the creditors.

11. The amount of ex-gratia and loan settlement shall be allotted to the concerned District Magistrate from the budgetary allocation of the Disaster Management Department.

12. The amount of ex-gratia shall be deposited with that Nationalized Bank which provides best deal to the next-of-kin of the deceased farmer.

13. The standing committee shall examine the documents and other evidence to determine the amount of loan settlement and come to a definitive conclusion before the loan is settled with the creditors. The mortgage deeds, if any, executed by the deceased with the creditors shall be returned forthwith to the next-of-kin by him and a deed of redemption shall be executed by him before the loan settlement.

14. The benefits under these Rules, if applicable, shall be extended to the distressed family within a period of one month from the date of receipt of the information of the suicide.

Policy of Rehabilitation of the farm distressed families

15. The standing committee in general and the District Magistrate in particular shall ensure that the officials of Revenue and Land Reforms Department as well as Agriculture Department work with the distressed families for at least one year or as long as it would be necessary to bring the families out of distress. The officials would assist the families in accessing agriculture credit, crop insurance benefits, agriculture technology, input use, diversification of agriculture, procurement of produce facilities etc. and address land issues affecting them.

16. The standing committee in general and the District Magistrate in particular shall ensure that the distressed families are covered under various development programs of agriculture and allied departments including Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), National Food Security Mission (NFSM), National Horticulture Mission (NHM), etc.

Measures to Prevent Farm Distress

17. The platform of State Level Bankers Committee (SLBC) and District Level Bankers Committee (DLBC) shall be used to vigorously pursue the promotion, extension and monitoring of institutional credit to the farmers in accordance with district credit plan and also for making such credit accessible to every eligible farmer.

18. The Agriculture Department shall ensure that benefits under Krishi Road Map of the State Government and other State and Central Government schemes related to agriculture are implemented in a focused manner in such areas which are vulnerable to farm distress on account of agro climatic and other socio-economic factors.

19. At the State level a High Level Standing Committee to suggest measures to the Government and concerned Departments to prevent farm distress and monitoring of its implementation shall be constituted under Agriculture Production Commissioner. The Secretary/ Principal Secretary of the Departments of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries Resources, Cooperation, Environment and Forest and Revenue and Land Reforms shall be the members of this committee. Director of Agriculture shall be the convener of the committee.

Interpretation and Removal of difficulties

20. If any difficulty arises in the interpretation of any of the provisions or implementation of this Scheme, the Disaster Management Department shall be competent to interpret it and issue

directions for its implementation. The decision of this department in all such matters shall be final and binding.

By Order of the Governor of Bihar
Vyas Ji,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 919-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>